खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सुख सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पैनल की नियुक्ति

5. **श्री राम नरेश यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक पैनल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे इन श्रमिकों को इस सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या सरकार पैनल की सिफारिशें प्राप्त होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में उन्हें तत्काल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाने के संबंध में अनुदेश जारी करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) सरकार ने खादी के उत्पादन में कार्यरत भिन्न-भिन्न खादी संस्थानों के श्रमिकों की सेवा शर्तों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है । यह देखा गया है कि इन श्रमिकों की नियुक्ति खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नहीं की जाती ।

(ख) इन श्रमिकों को वेतन खादी संस्थानों द्वारा दिया जाता है जो स्वैच्छिक संगठन है जिनके वेतनमान और सेवा शर्तों इत्यादि के सम्बन्ध में अपना संविधान और नियम लागू होते हैं ये पंजीकृत संस्थान हैं, अतः इनका एक अलग कानूनी अस्तित्व है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन संस्थानों के सेवा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। इन श्रमिकों को दिये जाने वाले वेतन के सम्बन्ध में सूचना सहज उपलब्ध नहीं है क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता पाने वाले ऐसे संस्थानों की संख्या लगभग 31000 है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । ऊपर "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । तथापि, के० वी० आई० सी० उत्तर प्रदेश खादी संस्थानों से अनुरोध कर रही है कि उत्तर प्रदेश दुकान अधिनियम के लाभ उनके श्रमिकों को भी दिये जाएं । के० वी० आई० सी० खादी की बिक्री में इन संस्थानों के लाभ में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहा है । इन उपायों से श्रमिकों को लाभ होगा ।

Discovery i of oil in Jaisalmer district of Rajasthan

6. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state;

(a) whether there is any positive indication t_0 strike oil in the Jaisalmer district of Rajasthan;

(b) if so, what are the results of recent drilling in the region by Oil India Limited; and

(c) by when the production is likely to commence at commercial level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI BHAJMAN BEHERA): (a) Exploration is being carried out both by Oil and Natural Gas Commission and Oil India Ltd. in Rajasthan. In, two wells *viz.* Ghotaru well No. 2 (by ONGC) and Tanot-2 (by Oil India Ltd.) in Jaisalmer Basin, there were indications of oil during testing, but these were not commercial strikes of oil.

(b) So far, four exploratory wells have been drilled by Oil India Ltd. in Tanot and Ramgarh area in the Jaisalmer district of Rajasthan. Of these, 3 wells have been drilled in the Tanot area, nn<i the fourth in the Ramgarh. So far, all the wells have given indications of gas. Currently, a well is under drilling at Dande-wala, where also indications of gas are